



आजादी से पहले के विकास कार्यक्रम

श्रीनिकेतन परियोजना (1914)

- 1914 में श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया
- ग्रामीण सेटिंग में शिक्षा पर अपने विचारों का विस्तार करने के लिए एक केंद्र विकसित करना।
- इस संस्थान को सरकारी मदद और सहायता नहीं मिल सकी।

गुड़गांव परियोजना (1920)

- 1920 में F.L.Brayne द्वारा शुरू किया।

मार्थानडम परियोजना (1921)

- 1921 में केरल के त्रावणकोर में शुरू किया गया
- डॉ स्पेंसर हैच द्वारा एक अमेरिकी कृषि समाजशास्त्र में विशेषज्ञता विशेषज्ञ।
- कृषि, जन स्वास्थ्य और शिक्षा में सर्वांगीण विकास।

सर्वोदय आंदोलन (1948-49)

- यह एक गांधीवादी अवधारणा थी और बंबई में बहुत उत्साह पैदा हुई।
- मुख्य विशेषताएं सादगी, अहिंसा, श्रम की पवित्रता और मानवीय मूल्यों का पुनर्निर्माण थे।
- इसका उद्देश्य जीवन स्तर को बढ़ाना, कृषि का वैज्ञानिक विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, साक्षरता का प्रसार, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्राम पंचायतों का विकास करना था।

भारतीय ग्राम सेवा (1945)

- शुरुआत न्यूयॉर्क के आर्थर टी मोशेर और बीएन गुप्ता ने की।
- उद्देश्य गांव के लोगों को व्यक्तियों, स्वयंसेवक नेताओं और स्थानीय एजेंसियों के विकास के द्वारा अपने ही गांव में सबसे अच्छा महसूस करने में सहायता करना और उन्हें खुद की मदद करने में प्रभावी होने के लिए स्थापित करना था।

स्वतंत्रता के बाद के युग के विकास कार्यक्रम

इटावा पायलट प्रोजेक्ट (1948)

- यूएसए के श्री अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया
- आत्मविश्वास और सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादक और सामाजिक सुधार की डिग्री जानने के लिए



नीलोखेड़ी परियोजना (1948)

- इसके डे द्वारा शुरू
- पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक नई टाउनशिप विकसित करने का उद्देश्य था
- इस परियोजना को शरणार्थियों की सहायता और सरकारों की सहायता से दलदली बंजर भूमि में बनाया गया था।

मजदूर मंज़िल

- एस.के. डे ने नीलोखेड़ी में टाउनशिप के निर्माण के लिए 'मजदूर मंज़िल' नामक नई योजना शुरू की
- इस योजना ने लोगों को दिया
 - (1) कृषि उपकरणों की तैयारी पर प्रशिक्षण
 - (2) कुटीर उद्योग
 - (3) बढ़ईगिरी

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) - 2 अक्टूबर 1952

- राजकोषीय आयोग (1949) और ग्रो मोर फूड जांच समिति (1952) की सिफारिशें
- उद्देश्य- (i) आर्थिक विकास, (ii) सामाजिक न्याय (iii) लोकतांत्रिक विकास
- 20 सितंबर, 1956 एक अलग केंद्रीय मंत्रालय सामुदायिक विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता बनाया गया था।
- सीडीपी- राष्ट्रीय स्तर का प्रशासन- अध्यक्ष पद पर पी.एम
- राज्य स्तर: अध्यक्षता मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय विस्तार सेवा (एनईएस) - 2 अक्टूबर, 1953

- उन क्षेत्रों में लागू किया गया जो सीडीपी द्वारा कवर नहीं किए गए थे
- उद्देश्य- गांव के लोगों के दृष्टिकोण को बदलना
- विकास कार्यक्रमों में लोगों को प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए

पंचायत राज व्यवस्था

- मद्रास राज्य ने 1957 की शुरुआत में एक पायलट परियोजना के रूप में इसकी कोशिश की
- इस राज्य में सफलता के आधार पर यह राजस्थान था जो 2 अक्टूबर, 1959 को पूरे राज्य को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत लाने के लिए अग्रणी बना

सघन कृषि जिला कार्यक्रम (आईएडीपी) - जुलाई 1960

- कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न के प्रति दृष्टिकोण। एक "पैकेज कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है
- उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा, उपकरण, ऋण आदि की प्रथाएं।



सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (आईएएपी) - 1964

उच्च उपज विविधता कार्यक्रम (HYVP)- 1966

- इन्हें उच्च विश्लेषण और संतुलित उर्वरक, सिंचाई, पौधों की सुरक्षा, बेहतर उपकरण आदि के अनुप्रयोग के साथ जोड़ा गया था जिसने देश में 'हरित क्रांति' संभव बनाई
- इस रणनीति के चरणबद्ध लॉन्चिंग के लिए शुरू में पंजाब, एचआर और यूपी के पश्चिमी हिस्सों का चयन किया गया था।
- गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। चावल उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना- 2 अक्टूबर 1975

- आज, आईसीडीएस योजना बचपन के विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है

प्रशिक्षण एवं यात्रा प्रणाली (टीएंडवी) - 1979

- एक पेशेवर विस्तार सेवा का निर्माण करना जो किसानों को उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने और कृषि विकास के लिए उचित सहायता प्रदान करने में सहायता करने में सक्षम होगा

संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम (आईवीएलपी) - 1995

- आईवीएलपी आईसीएआर द्वारा एक अभिनव कार्यक्रम है
- वैज्ञानिकों को कृषक समुदाय के साथ सीधी बातचीत करने में मदद करना ताकि किसानों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित की जा सकें

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP)- 1998-2003

- विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP) का उद्देश्य अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में सुधार करना है।
- NATP के अनुसंधान घटक आईसीएआर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है

राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

- DPAP 1973-74 में शुरू किया गया था
- उन क्षेत्रों के सामने आने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए जो लगातार सूखे की स्थिति से पीड़ित हैं

डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम (डीडीपी)

- डीडीपी 1977-78 में शुरू किया गया था
- मरुस्थलीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए .



एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

- आईडब्ल्यूडीपी 1989-90 से कार्यान्वयन के अधीन है।
- आईडब्ल्यूडीपी के तहत परियोजनाएं आम तौर पर उन क्षेत्रों में स्वीकृत होती हैं जो डीडीपी के तहत शामिल नहीं होते हैं

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRISEM)

- 15 अगस्त, 1979 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)

- 1978 के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया और 1980 के दौरान लागू किया गया।
- गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके कौशल सेट विकसित करने के अवसर ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास (DWCRA)

- वर्ष 1982 से 50 जिलों में शुरू की गई वर्ष के दौरान आईआरडीपी की उप योजना।
- यह आंशिक रूप से यूनिसेफ द्वारा समर्थित है और संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित है
- यह IRDP और TRYSEM के साथ संयोजन के रूप में संचालित

जवाहर रोजगार योजना (जेआरी)

- इसे 1 अप्रैल, 1989 को पेश किया गया था
- यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) का एकीकरण है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

- 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च किया
- जिससे ग्रामीण गरीबों को टिकाऊ आय प्रदान की जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, ग्रामीण गरीबों की क्षमता पर निर्माण कार्यक्रम।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी [एटमा]:

- एटमा जिला स्तर पर एक पंजीकृत सोसायटी जिम्मेदार पॉट प्रौद्योगिकी प्रसार है।
- यह कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली के दिन प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत दिन [एटीएस]
- 2005 में शुरू किया।
- जिलाधिकारी एटमा के बोर्ड के अध्यक्ष हैं।